Aishwarya College of Education (Law)

Affiliated to Dr B.R Ambedkar Law University Jaipur

Sector-A Kamla Nehru Nagar, Jodhpur (Rajasthan) Email- info@aishwaryacollege.edu.in Phone-02912760175

NOTICE

It is informed to all students of LL.B SECOND YEAR that as per PAPER VIII MEDIATION CONCILIATION AND ARBITRATION of your syllabus. It is mandatory for every student to prepare Moot Problem on Arbitration settlement. Which shall carried 20 marks:

ARBITRATION MOOT-PROBLEM

SHAH BROTHERS Vs. CHANDRAJI SHARMA AND OTHERS

Facts of dispute:-

Jodhpur Development Authority issued a notice with respect to holding a public auction of plots in Development Complex, Chokha Road, Jodhpur. The auction was to take place on March 15, 2021. The appellant bid the highest in the auction and the bidding amount was 25,10,000. The aforesaid bid was accepted and the appellant was asked to deposit bidding amount and submit a relevant stamp for the execution of lease deed by a rightful authority. However, the appellant did not deposit amount and submit paper before prescribed date. Because of this error, the initially deposited premium of rupees 6,27,500/- was confiscated. Resultantly, the appellant challenged the order of confiscation and requested

Jodhpur Development Authority to get the matter expedited by an arbitrator under Section 21 of Arbitration Act. Meanwhile, the State Government transferred the Development Complex Scheme but this request had been accepted. On June 8, 2022, Shri G.S. Sudarshan, who was a retired I.A.S., was appointed arbitrator who paased an award in favour of the appellant in this respect. Then, Respondent no.1, considering this decision a severe loss, filed an appeal in Rajasthan High Court and the Court repealed this award. The offended appellant, then, filed a Public Interest Litigation in the bench of Rajasthan High Court under Article 226 of Indian Constitution.

Facts in issue:-

- 1) Was abovementioned matter worthy of being resolved by an arbitrator?
- 2) Is appointment of arbitrator legitimate /legal or not?
- 3) What is the propriety of Section 21 of Arbitrary Act?
- 4) Was award appealable and worthy of being heard by the High Court?
- 5) Can a PIL be filed against the decison of appeal?



मध्यस्थता विवाद - समस्या

शाह ब्रदर्स बनाम चंद्राजी शर्मा व अन्य

वाद के तथ्य :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण ने विकास परिसर, चोखा रोड, जोधपुर में भूखंडों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया। नीलामी 15 मार्च, 2021 को होनी थी। नीलामी में अपीलकर्ता ने सबसे अधिक बोली लगाई और बोली राशि 25, 10,000/-रुपये । उपरोक्त बोली को स्वीकार कर लिया गया और अपीलकर्ता को बोली राशि जमा करने और एक उचित प्राधिकारी द्वारा लीज डीड के निष्पादन के लिए एक प्रासंगिक स्टाम्प जमा करने के लिए कहा गया। हालांकि, अपीलकर्ता ने राशि जमा नहीं की और ना ही निर्धारित तिथि पर कागज जमा किया। इस त्रृटि के कारण, प्रारंभिक रूप से जमा किए गए 6,27,500/- रुपये के प्रीमियम को जब्त कर लिया गया। नतीजतन, अपीलकर्ता ने अधिहरण के आदेश को च्नौती दी और जोधप्र विकास प्राधिकरण से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के तहत एक मध्यस्थ द्वारा मामले को हल किए जाने के का अन्रोध किया। इस बीच, राज्य सरकार ने विकास परिसर योजना को स्थानांतरित कर दिया ,लेकिन यह अन्रोध स्वीकार कर लिया गया था। 8 जून, 2022 को, श्री जी.एस. सूदर्शन, जो एक सेवानिवृत्त आई.ए.एस. थे, को मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिन्होंने इस संबंध में अपीलकर्ता के पक्ष में एक "पंचाट" पारित किया। फिर, प्रतिवादी नंबर 1 ने इस फैसले को एक गंभीर नुकसान मानते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की और अदालत ने इस "पंचाट" को निरस्त कर दिया। तब आहत अपीलकर्ता ने भारतीय



संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की।

विवादित प्रश्न:-

- 1) क्या उपरोक्त मामला एक मध्यस्थ द्वारा हल किए जाने के योग्य था?
- 2) मध्यस्थ की नियुक्ति वैध/कानूनी है या नहीं?
- 3) मनमाना अधिनियम की धारा 21 का क्या औचित्य है?
- 4) क्या पुरस्कार अपीलीय था और उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के योग्य था?
- 5) क्या अपील के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जा सकती है?

16,2,22

(Principal)

Copy To:-

- Notice Board/WEBSITE
- Department of law for necessary action
- Students Circulation

